रिविजनल सिविल

ए. डी. कोशल, जे के समक्ष

भारत संघ - याचिकाकर्ता।

बनाम

बर्मा नंद, - *उत्तरदाता।*

1973 का सिविल संशोधन संख्या 264।

28 मार्च, 1974।

विशिष्ट राहत अधिनियम (1963 का 47) - धारा 34, परंतुक - भारत का संविधान - अनुच्छेद 311 - अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करते हुए सेवा से हटाने का आदेश - वेतन की बकाया राशि को शून्य घोषित करने का आदेश - इस तरह के घोषित वाद का दावा नहीं किया जाता है - क्या धारा 34 के परंतुक द्वारा रोक दिया गया है - वेतन के बकाया की वसूली के लिए राहत - क्या परंतुक की शर्तों में" और राहत " है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 उन मामलों की संपूर्ण नहीं है जिनमें न्यायालय द्वारा एक घोषणा दी जा सकती है। जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करते हुए सेवा से हटाने के आदेश को शून्य घोषित करने के लिए एक मुकदमा दायर किया जाता है, तो ऐसा मुकदमा किसी क़ानून के सही निर्माण की घोषणा करने और संविधान के उल्लंघन में किए गए कार्य को शून्य घोषित करने के लिए होता है। हालांकि यह मुकदमा बकाया वेतन के दावे के बिना स्पष्ट घोषित करने के लिए भी है, लेकिन यह अधिनियम की धारा 34 की सीमाओं के बाहर आता है, जिसका परंतुक मांगी गई राहत के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यहां तक कि जब कोई व्यक्ति यह घोषणा करना चाहता है कि वह अधिनियम की धारा 34 के अर्थ के भीतर किसी भी संपत्ति के किसी भी चरित्र या किसी भी अधिकार का हकदार है और घोषणा से बहने वाली राहत उसके लिए खुली है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना नहीं की गई है, तो परंतुक उस मामले की ओर आकर्षित नहीं होगा यदि घोषणा की राहत अपने आप में एक वास्तविक और प्रभावी राहत है। बकाया वेतन की वसूली अधिनियम की धारा 34 के परंतुक के संदर्भ में "और राहत" नहीं है, क्योंकि सेवा से हटाने के आदेश की घोषणा शून्य है, यह अपने आप में एक पूरी तरह से प्रभावी राहत है जो बकाया वेतन की वसूली के लिए प्रार्थना के अभाव में अर्थहीन नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 *और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227* के तहत श्री आई. पी. आनंद, उप-न्यायाधीश, *प्रथम* श्रेणी, अंबाला शहर के दिनांक 2 नवंबर, *1972 के आदेश में संशोधन के लिए* याचिका, *जिसमें प्रतिवादी के खिलाफ और वादी के पक्ष में निर्णय लिया गया था।*

याचिकाकर्ता की ओर *से रतन लाल गर्ग, एडवोकेट।*

प्रतिवादी की ओर *से एस खोजी, वकील।*

निर्णय

कोशल, जे - सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह याचिका अंबाला शहर के अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी श्री आईपी आनंद द्वारा पारित 2 नवंबर, 1972 के एक आदेश की समीक्षा की मांग करती है, जिसमें घोषणा के लिए एक मुकदमे में उत्पन्न प्रारंभिक मुद्दे पर फैसला किया गया था।

2. कुछ तथ्य विवादित नहीं हैं और यहां बताए जा सकते हैं। वादी बर्मा नंद, जो मुझसे पहले प्रतिवादी हैं, 2 जनवरी, 1953 को एक कुशल फिटर के रूप में जगाधरी रेलवे कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने 19 अगस्त, 1968 तक उस क्षमता में काम करना जारी रखा, जब उन पर गंभीर कदाचार का आरोप लगाया गया। अंततः, जगाधरी रेलवे वर्कशॉप के कार्य प्रबंधक ने 24 फरवरी, 1969 को एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सेवा से हटा दिया। उन्होंने अपील दायर की, लेकिन अपीलीय प्राधिकारी ने 31 जुलाई, 1969 को उसे खारिज कर दिया।

3. अपनी याचिका में वादी ने उन्हें सेवा से हटाने के आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों और उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है। 10 मार्च, 1972 को स्थापित वाद में की गई प्रार्थना यह है कि इस आशय की घोषणा की जाए कि वादी को जगाधरी वर्कशॉप के वर्क्स मैनेजर द्वारा 24 फरवरी, 1969 को पारित किए गए आदेश के अनुसार रेलवे वर्कशॉप, जगाधरी में कुशल फिटर के रूप में अभी भी सेवा में माना जाएगा और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उसकी अपील को अस्वीकार कर दिया जाएगा। 31 जुलाई, 1969 की तारीख अवैध, अमान्य, निष्क्रिय है और वादी या किसी अन्य राहत के लिए बाध्यकारी नहीं है।

मुकदमे में एकमात्र प्रतिवादी भारत संघ है जिसकी ओर से वादी को हटाने को उचित ठहराने की मांग की गई है। लिखित बयान में ली गई प्रारंभिक आपत्तियों में से एक में लिखा है:

"यह मुकदमा आदेश 2 सीपीसी और विशिष्ट राहत अधिनियम द्वारा निषिद्ध है,

> क्योंकि वादी केवल घोषणा और निषेधाज्ञा की राहत के साथ-साथ बकाया वेतन का हकदार बन जाएगा परिणामी राहत के बिना घोषणा सुनवाई योग्य नहीं है।"

आपत्ति को खुशी से नहीं कहा गया है, लेकिन पार्टियों के बीच यह आम आधार है कि यह नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश II के नियम 2 और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 (इसके बाद 1963 अधिनियम के रूप में संदर्भित) को मुकदमे के लिए एक रोक के रूप में पेश करता है क्योंकि वादी को सेवा से हटाने की तारीख से ^ सेवा से हटाए जाने की तारीख से बकाया वेतन का दावा करने में विफल रहता है। मुकदमे की संस्था के बारे में। इस आपत्ति के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने निम्नलिखित प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया:

> "क्या मुकदमा विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 और आदेश 2, नियम 2, सीपीसी द्वारा प्रतिबंधित है?"

यह मानते हुए कि मुकदमा वर्तमान से सुनवाई योग्य था, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने विवादित आदेश के माध्यम से वादी के पक्ष में इस मुद्दे का फैसला किया।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री आरएल गर्ग ने मेरे समक्ष स्पष्ट रूप से और बहुत सही ढंग से स्वीकार किया है कि वर्तमान मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश II के नियम 2 के आवेदन का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह नियम केवल यह निर्धारित करता है कि यदि कोई वादी पूरी राहत की मांग नहीं करता है जिसके लिए वह हकदार है। एक का सम्मान कारण कार्रवाई पर जिस पर वह मुकदमा करता है, वह करेगा नहीं बाद में मुकदमा के लिए पद छोड़ दिया अदालत की अनुमति के बिना झूठ बोला। अब, यदि बकाया वेतन के लिए राहत उसी कार्रवाई के कारण से आती है जो घोषणात्मक राहत के दावे का आधार है, तो नियम 2 के प्रावधान लागू होंगे यदि *वादी बाद में उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए मुकदमा लाता है,* एक राहत जिसका उसने अब दावा नहीं किया है। जब तक वादी इस तरह का दूसरा मुकदमा नहीं लाता है, तब तक नियम 2 की प्रयोज्यता आकर्षित नहीं होती है और इसलिए, इसे किसी भी तरह से वर्तमान मुकदमे को प्रतिबंधित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

(5) 1963 अधिनियम की धारा 34 का प्रासंगिक भाग, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया एकमात्र विवाद आधारित है, संदर्भ की सुविधा के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

"34. कोई भी व्यक्ति जो किसी कानूनी चरित्र का हकदार है, या किसी संपत्ति के किसी भी अधिकार का हकदार है, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है जो उसे अपनी उपाधि से इनकार करता है, या अस्वीकार करने में रुचि रखता है।

चरित्र या अधिकार, और न्यायालय अपने विवेकाधिकार में एक घोषणा कर सकता है कि वह इस तरह का हकदार है और वादी को ऐसे मुकदमे में कोई और राहत मांगने की आवश्यकता नहीं है:

परन्तु कोई भी न्यायालय ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगा जिसमें वादी, केवल शीर्षक की घोषणा से अधिक राहत प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण, ऐसा करने से चूक जाए।

* * * * * "

श्री गर्ग ने मेरे समक्ष जोरदार दलील दी है कि यदि और जैसे ही वादी को घोषणा की अनुमति दी जाती है, तो वह वेतन का हकदार हो जाता है, जो कि धारा 34 के परंतुक के अर्थ के भीतर एक और राहत है और इसका परिणाम यह है कि घोषणा के लिए मुकदमा इस कारण से सुनवाई योग्य नहीं है कि परंतुक में क्या कहा गया है।

जवाब में, वादी-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने दो बिंदु रखे हैं:

(1) धारा 34 उन मामलों का संपूर्ण नहीं है जिनमें न्यायालय द्वारा एक घोषणा दी जा सकती है; ताकि यदि कोई मुकदमा धारा 34 द्वारा विचार ति प्रकार का नहीं है, तो न्यायालय द्वारा केवल एक घोषणा दी जा सकती है, भले ही वादी द्वारा 'आगे की राहत' का दावा किया जा सके। वर्तमान मामले में मुकदमा धारा 34 के दायरे में नहीं आता है।

(2) यहां तक कि अगर वर्तमान मुकदमा धारा 34 के दायरे में आता है, तो भी इसे धारा के परंतुक द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, क्योंकि 'आगे की राहत' का अर्थ एक राहत है जो दावा की गई घोषणा में निहित है, एक राहत है जिसके बिना घोषणा त्मक राहत अप्रभावी, निरर्थक और अव्यावहारिक होगी। वादी द्वारा मांगी गई घोषणा एक आत्मनिर्भर राहत है, जो उसे सेवा में बने रहने का हकदार बनाएगी और वेतन के बकाया की वसूली के लिए प्रार्थना के अभाव में भी पूरी तरह से प्रभावी होगी, इसलिए, इसे परंतुक के अर्थ के भीतर 'आगे राहत' नहीं माना जा सकता है।

पक्षकारों के वकीलों को विस्तार से सुनने के बाद, मेरी राय है कि प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा रखे गए दोनों बिंदु अच्छी तरह से स्थापित हैं और याचिकाकर्ता

की ओर से उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(6) श्री खोजी द्वारा प्रस्तुत पहले मुद्दे पर अग्रणी मामला *फिशर बनाम काउंसिल में भारत के राज्य सचिव (1)*, जिसमें लॉर्ड मैकनाघटेन ने विशिष्ट राहत अधिनियम (1877) का अधिनियम 1, (और इसके बाद 1877 अधिनियम कहा जाता है) की धारा 42 के बारे में कहा, जिसके प्रावधान 1963 अधिनियम की धारा 34 के समान हैं:

> "अब, पहली बात तो यह है कि कम से कम यह संदेह पैदा हो सकता है कि क्या वर्तमान मुकदमा विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 के दायरे में है। उस खंड की उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। इसका उद्देश्य 1852 के चांसरी प्रक्रिया अधिनियम (15 और 16 वियत सी 86) की धारा 50 के प्रावधानों को अन्य बातों के साथ पेश करना था।
>
> न्यायिक निर्णय द्वारा निर्धारित। 1832 के अधिनियम से पहले, सामान्य मुकदमों में न्यायालय द्वारा यह प्रथा नहीं थी कि वह राहत के परिचयात्मक के अलावा अधिकार की घोषणा करे, जिसे वह प्रशासित करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन
>
> वर्तमान मुकदमा एक ऐसा मुकदमा है जिस पर 1852 के अधिनियम से पहले कोई आपत्ति नहीं ली जा सकती थी। यह पदार्थ ए में है किसी क़ानून के सही निर्माण की घोषणा की जाए, और क़ानून के उल्लंघन में किए गए कार्य को सही तरीके से अमान्य और बिना किसी प्रभाव के समझा जाए। यह उस तरह का घोषणात्मक आदेश नहीं है जो अधिनियम के निर्माताओं के दिमाग में था।"

अगला मामला *प्रताप सिंह बनाम भबूते सिंह (2)* का है। उस मामले

(1) (1899) 26 आईए 16 (पी.सी.)

(2) (1913) 40 एलए। 182 (पी.सी.)

में वादी का मुकदमा इस घोषणा के लिए था कि उनकी ओर से किए गए कुछ पूर्व-मुकदमों का समझौता जब वे नाबालिग थे और उसके तहत पारित डिक्री उन पर बाध्यकारी नहीं थे, धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे और उन कार्यवाहियों में शामिल थे जिनमें वे व्यावहारिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। न्यायिक समिति के समक्ष प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि मुकदमा केवल घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के उद्देश्य से दायर किया गया था क्योंकि यह प्रार्थना नहीं करता था कि डिक्री को रद्द कर दिया जाना चाहिए; लेकिन यह मानते हुए कि यह केवल एक

घोषणात्मक डिक्री के लिए पूछने में सही तरीके से तैयार किया गया था, अदालत के पास ऐसी घोषणा को देने या अस्वीकार करने का विवेक था। न्यायिक समिति ने पाया कि 1877 अधिनियम की धारा 42 इस मामले से संबंधित नहीं है और यह उस धारा के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करने का सवाल नहीं था, उन्होंने वादी को एक डिक्री दी, जिसमें शिकायत की गई डिक्री को रद्द कर दिया गया और घोषणा की गई कि

समझौता और जिन आदेशों की शिकायत की गई थी, वे अपीलकर्ताओं के लिए बाध्यकारी नहीं थे। इसलिए, वह मामला भी इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि 1963 अधिनियम की धारा 34 (जैसा कि पहले ही बताया गया है, 1877 अधिनियम की धारा 42 से मेल खाती है) उन मामलों की संपूर्ण नहीं है जिनमें वादी को एक घोषणा दी जा सकती है। इस प्रस्ताव को *आंध्र विश्वविद्यालय बनाम कोराडा दुर्गा लक्ष्मी मनोहरम, (3)* में राघव राव, जे. द्वारा सही माना गया था, जो एक कॉर्पोरेट निकाय, आंध्र विश्वविद्यालय के तहत वादी को सेवा से गलत तरीके से बर्खास्त करने में पड़े अनुबंध के उल्लंघन की घोषणा के लिए एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा था। प्रतिवादी विश्वविद्यालय की ओर से उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि यह मामला 1877 अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों को

(3) ए.आई.आर. 1951 मैड. 870

आकर्षित करता है और इसके परंतुक से प्रभावित होता है ताकि वादी को नुकसान के लिए मुकदमा करना अनिवार्य हो, हालांकि, नाममात्र, और यहां तक कि उस धारा और इसके परंतुक के अलावा, विचाराधीन प्रकार की स्पष्ट घोषणा के लिए एक मुकदमा कानून के लिए अज्ञात था। यह मानते हुए कि मुकदमा 1877 के अधिनियम के दायरे से बाहर है, विद्वान न्यायाधीश ने कहा:

> "यह धारा केवल किसी पक्ष के कानूनी चरित्र या स्थिति या किसी भी संपत्ति के रूप में उसके अधिकार की न्यायिक घोषणा के लिए एक मुकदमा मानती है, और यह मुकदमा उस तरह का नहीं है। जैसा कि श्री नरसराजू ने ठीक ही तर्क दिया है, इस न्यायालय के सुस्थापित प्राधिकारी के अनुसार यह धारा सभी संभावित घोषणात्मक मुकदमों से सम्पूर्ण नहीं है; लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या वर्तमान खंड के संदर्भ के अलावा अन्य रूप से बनाए रखने योग्य है। यह मुझे विवाद की दूसरी शाखा पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है।

कई तय किए गए मामलों की समीक्षा करने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने कहा

:-

> "इसलिए, स्थिति यह है कि मेरे लिए ऐसा कोई मामला नहीं है जो यह मानता है कि प्रतिवादी की सेवा से वादी को गलत तरीके से बर्खास्त करने में निहित अनुबंध के उल्लंघन की घोषणा के लिए एक मुकदमा इस तरह के उल्लंघन के लिए नुकसान के दावे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से वादी के चरित्र की पुष्टि के दृष्टिकोण से कल्पना की गई है; इस तरह की गलत बर्खास्तगी से कलंकित स्थिति बरकरार नहीं रखी जा सकती।

प्रताप सिंह बनाम *भबुते सिंह* (2) और *फिशर बनाम काउंसिल में भारत के राज्य सचिव (1)* में लॉर्ड मैकनाघटेन द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष निकाले गए अवलोकन। *भारत के लिए* (1) को वेमारेड्डी रामराघव रेड्डी और अन्य *बनाम भारत* में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था / *कोंडुरु सेशु रेड्डी और अन्य* (4) जिसमें ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव को स्पष्ट शब्दों में दोहराया गया था। लॉर्डशिप के समक्ष मामले में घोषणा की मांग की गई थी कि एक समझौते पर पारित डिक्री का हिस्सा जिसके तहत कुछ मंदिर संपत्तियों को प्रतिवादियों की निजी संपत्ति घोषित किया गया था जो मंदिर का प्रबंधन कर रहे थे क्योंकि इसके ट्रस्टी देवता के लिए बाध्यकारी नहीं थे। सूट एक उपासक द्वारा लाया गया था। प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि ^ वादी किसी भी कानूनी चरित्र या किसी भी संपत्ति के अधिकार के हकदार व्यक्ति के रूप में मुकदमा नहीं कर रहा था, बल्कि देवता के लाभ के लिए मुकदमा कर रहा था ताकि मुकदमा 1877 अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों द्वारा रोक दिया जाए। लॉर्ड मैक-नागटेन की उक्त टिप्पणियों का हवाला देने और *प्रताप सिंह* बनाम भबुते *सिंह का उल्लेख करने के बाद,* (2) उनके लॉर्डशिप ने कहा:

> "हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में वादी द्वारा जिस चरित्र की डिक्री मांगी गई है, वह वह नहीं है जिसके लिए 1852 के अधिनियम द्वारा प्रदत्त अतिरिक्त शक्तियों की आवश्यकता चांसरी की अदालत द्वारा की गई थी। चोट की शिकायत यह थी कि अदालत ने 1950 के ओपी नंबर 3 में समझौते को दर्ज करके, देवता को कुछ ट्रस्ट संपत्तियों को उसके वर्तमान शीर्षक से वंचित कर दिया है। वादी जो राहत चाहता है वह एक घोषणा के लिए है कि समझौता डिक्री अमान्य और शून्य थी और यदि ऐसी घोषणा दी जाती है तो देवता को ट्रस्ट की संपत्तियों में अपने वर्तमान अधिकारों में बहाल कर दिया जाएगा। इस चरित्र की घोषणा, अर्थात्,

कि समझौता डिक्री देवता पर बाध्यकारी नहीं है, अपने आप में एक पर्याप्त राहत है और इसका तत्काल बलपूर्वक प्रभाव पड़ता है। *फिशर बनाम काउंसिल में भारत के राज्य सचिव (1)*में इस तरह की घोषणा अपील का विषय थी । और विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 के दायरे से बाहर आता है और डब्ल्यूएच 1 सिविल के सामान्य प्रावधानों द्वारा शासित किया जा सकता है। धारा 9 या 0.7, आर. 7 जैसी प्रक्रिया संहिता।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ के निर्णय में वेमारेड्डी के मामले *(4) के अनुपात का अनुसरण किया गया था, जिसे वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी लिमिटेड*, बनाम *रामेश्वर प्रसाद* (5) *के रूप में रिपोर्ट किया गया था*। जिसमें प्रश्न इसमें वही शामिल था जो मेरे समक्ष उठा था क्योंकि वादी ने यह घोषणा करने की मांग की थी कि प्रतिवादी लिमिटेड कंपनी द्वारा© उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश अमान्य, अवैध और निष्क्रिय था क्योंकि यह प्रासंगिक स्थायी आदेश का उल्लंघन था। प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि मुकदमे में दावा की गई राहत को_अन्य बातों के साथ-साथ *1877 अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के मद्देनजर नहीं दिया जा सकता* है। बी. डी. गुप्ता और हरि स्वरूप, जे.जे. ने लॉर्ड मैकनाघटेन की उपरोक्त टिप्पणियों और वेमारेड्डी के मामले (4) में सुप्रीम कोर्ट के

(4)ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 436.

(5) 1971 श्रम और औद्योगिक मामले 1447।

उनके लॉर्डशिप द्वारा उनके अनुमोदन पर ध्यान दिया और फिर कहा:

"वर्तमान मामला भी एक है जिसमें वादी मांग कर रहा है कि स्थायी आदेश के उल्लंघन में प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश को शून्य घोषित किया जाए और इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए धारा 42 के प्रावधान इस मामले में आकर्षित नहीं होंगे और विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 के आधार पर वादी को दावा की गई राहत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(7) मैं जिस मुकदमे से चिंतित हूं, वह वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करते हुए किए गए कार्य को अमान्य घोषित करने और इसका कोई प्रभाव

नहीं होने का मामला है। *फिशर बनाम काउंसिल में भारत के राज्य सचिव (1)* में लॉर्ड मैकनघटेन के अवलोकन इसलिए इस पर पूरी तरह से लागू होते हैं। यह एक मुकदमा भी है जिसमें वादी द्वारा मांगी गई घोषणा की राहत अपने आप में तत्काल कार्रवाई के लिए एक पर्याप्त राहत है। *इसलिए, वेमारेड्डी* (4) *के मामले* में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप के निर्णय का अनुपात, स्पष्ट रूप से इसकी ओर आकर्षित होता है। *आंध्र विश्वविद्यालय बनाम कोराडे दुर्गा लक्ष्मी मनोहरम* (3) और *द वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी लिमिटेड बनाम रामेश्वर प्रसाद* (5) में जो कुछ निर्धारित किया गया है, उसके बारे में भी यही सत्य है । इस प्रकार मेरी राय है कि यह मामला 1963 के अधिनियम की धारा 34 की सीमाओं से बाहर है। जो अदालत द्वारा मांगी जा रही राहत के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा।

(8) अब मैं उन निर्णयों की जांच करूंगा जिनका उल्लेख प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री खोजी ने उनके द्वारा रखे गए दूसरे बिंदु के समर्थन में

किया है। दिल्ली *राज्य बनाम भारत संघ* (6), *में* फलशॉ सी.जे., और टेक चंद, जे. द्वारा तय किया गया, वादी दिल्ली सशस्त्र पुलिस में एक निरीक्षक के रूप में कार्यरत था। उनकी नियुक्ति अस्थायी थी और 15 अक्टूबर, 1952 को उन्हें पुलिस महानिरीक्षक द्वारा छुट्टी दे दी गई क्योंकि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। मई, 1956 में, उन्होंने यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया कि उनकी बर्खास्तगी भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण शून्य थी और वह अभी भी पुलिस निरीक्षक के रूप में सेवा में थे। यह मानते हुए कि मुकदमा 1877 अधिनियम की धारा 42 के परंतुक से प्रभावित नहीं हुआ था, अदालत की ओर से बोलने वाले फालशॉ, सीजे ने कहा:

> "मेरी राय में यदि कोई सरकारी कर्मचारी यह घोषणा करने के लिए मुकदमा करता है कि उसकी सेवाओं की समाप्ति ऐसी गंभीर त्रुटियों से ग्रस्त है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और परिणामस्वरूप उसे पूरे समय सेवा में रहने के रूप में माना जाता है, तो उसके लिए वेतन के लिए मुकदमा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यदि वह अपनी घोषणा के साथ सफल होता है तो अन्य परिणाम स्वचालित रूप से पालन करते हैं। "

यद्यपि फालशॉ, सी.जे. ने ऐसा कहा था, लेकिन उनका मतलब यह प्रतीत होता है कि जब कोई व्यक्ति यह घोषणा करता है कि वह 1877 अधिनियम की धारा 42 के अर्थ के भीतर किसी भी संपत्ति के किसी भी चरित्र या किसी भी अधिकार का हकदार है और घोषणा से

(6) 1961 के एलपीए नंबर 90-डी का फैसला 8 मार्च, 1963 को किया गया।

मिलने वाली राहत उसके लिए खुली है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना नहीं की गई है, परंतुक इस मामले की ओर आकर्षित नहीं होगा यदि घोषणा का संदर्भ अपने आप में एक वास्तविक और प्रभावी राहत है।

एक अन्य मामला जो सीधे तौर पर सामने आया है, वह है *लेफ्टिनेंट कर्नल जी एस दत्ता* बनाम *भारत संघ (7)*का मामला।. उस मामले में सेवा से सेवानिवृत्त हुए वादी ने यह घोषणा करने की मांग की कि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 7 जून, 1953 के बजाय 16 जुलाई, 1954 थी, और वह तदनुसार अपनी पेंशन में वृद्धि के हकदार थे। उन्होंने भारत संघ के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की। एक तर्क उठाया गया था कि 1877 अधिनियम की धारा 42 का परंतुक मुकदमे के लिए एक रोक था क्योंकि वादी ने मुकदमे की तारीख तक अपनी पेंशन की बकाया राशि के लिए नहीं पूछा था। परंतुक पर विचार करते हुए, जानकीनाथ भट, जे. ने कहा:

"जोर 'आगे राहत' शब्दों पर है। मेरी राय में आगे राहत का मतलब ऐसी राहत होगी जो दावा की गई मूल घोषणा में निहित है, एक राहत जिसके बिना घोषणात्मक राहत का दावा अप्रभावी, निष्फल और अव्यवहारिक होगा। इस परंतुक को लागू करने का एक विशिष्ट मामला वह है जहां कोई व्यक्ति स्वामित्व का दावा करता है कुछ संपत्ति लेकिन उसके कब्जे से बाहर है, स्वामित्व की मात्र घोषणा डिक्री को निरर्थक, निष्फल और कोई सार्थक परिणाम देने में असमर्थ बना देगी, क्योंकि प्रभावी डिक्री जो पारित की जा सकती है वह संपत्ति के कब्जे के संबंध में है। यदि कब्जा प्रतिकूल पक्ष के पास ही रहने दिया जाता है और

वादी के पक्ष में मात्र घोषणा पत्र जारी कर दिया जाता है तो डिक्री जारी कर दी जाती है अर्थहीन होगा. यही इस परंतुक का अभिप्राय और इसके अंतर्निहित सिद्धांत हैं।"

(7) ए.आई.आर 1966 जे. एवं के. 124

अपने समक्ष मामले के परंतुक की इस व्याख्या को लागू करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने कहा:

> "वर्तमान मामले को बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है और निम्नलिखित तरीके से व्याख्या की जा सकती है। यदि वादी को यह घोषणा मिलती है कि वह पेंशन की बढ़ी हुई दर का हकदार है, तो यह डिक्री वादी के जीवनकाल के लिए लागू होगी, क्योंकि वह न केवल मुकदमा शुरू होने की तारीख तक, बल्कि अपने जीवन के अंत तक बढ़ी हुई पेंशन का हकदार होगा। यदि वह एक निश्चित राशि का दावा करने से चूक जाता है जिसे वह मुकदमे की संस्था तक दावा कर सकता था, तो यह घोषणा आदेश को अर्थहीन और निष्फल नहीं बना देगा, क्योंकि डिक्री में डिक्री की तारीख के बाद भविष्य के लिए पेंशन की बढ़ी हुई दर के लिए उसके लिए कार्रवाई के आवर्ती कारण की परिकल्पना की जाएगी। मुझे लगता है कि वादी का मामला विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 के परंतुक से प्रभावित नहीं है, लेकिन मुकदमा शुरू होने तक की अवधि के लिए बढ़ी हुई दर के बकाया के लिए सेवानिवृत्ति के बाद उसके द्वारा मुकदमा दायर करने पर नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 2, नियम 2 के तहत रोक लगा दी जाएगी।

अत्यंत सम्मान के साथ मैं लेफ्टिनेंट कर्नल दत्ता के मामले (7) *में जानकीनाथ भट, जे द्वारा 1877 अधिनियम की धारा 42 (* 1963 अधिनियम की धारा 34 के अनुरूप) पर लगाए गए हस्तक्षेप से पूर्ण रूप से सहमत हूं और इसके आधार पर यह कहना चाहूंगा कि बकाया वेतन की वसूली के लिए राहत 1963 अधिनियम की धारा 34 के परंतुक की शर्तों के भीतर 'आगे राहत' नहीं है। घोषणा

वादी द्वारा मांगी गई यह पूरी तरह से प्रभावी राहत है, जो बकाया वेतन की वसूली के लिए प्रार्थना के अभाव में अर्थहीन नहीं है।

(9) श्री गर्ग लेफ्टिनेंट कर्नल दत्ता के मामले (7) *के साथ-साथ दिल्ली राज्य बनाम भारत संघ* (6) के *मामले के अनुसार* सही कानून निर्धारित नहीं करता है। इस संबंध में वह *जुगराज सिंह और एक अन्य वी जसवंत सिंह और अन्य* (8) *पर भरोसा करता* है। जिनमें तथ्य ये थे। भाग सिंह नाम के एक व्यक्ति ने वर्ष 1923 में रण जंग सिंह के लिए कुछ जमीनें गिरवी रख दीं। भाग सिंह के एक बेटे द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के बल पर, एक वकील एस. करतार सिंह चावला ने 30 मई, 1963 को जसवंत सिंह और अन्य के पक्ष में भूमि के संबंध में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया। बिक्री विलेख को बाद में पंजीकृत किया गया जिसके बाद बंधक के मोचन के लिए पंजाब मोचन मोचन अधिनियम, 1913 (इसके बाद पंजाब अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 9 के तहत लागू किया गया। उन्होंने बंधक के तहत देय पूरी राशि कलेक्टर की अदालत में जमा कर दी, जिसने 6 अगस्त, 1963 को बंधक के मोचन का आदेश दिया। मूल बन्धकों के पुत्रों ने 7 अगस्त, 1963 को पंजाब अधिनियम की धारा 12 के अधीन मुकदमा दायर किया और वाद में उनके द्वारा दावा की गई राहत को इसके पैरा 10 में इस प्रकार कहा गया था:

"वादी प्रार्थना करते हैं कि इस आशय की घोषणा के लिए एक डिक्री कि प्रतिवादी न तो उपरोक्त भूमि के मालिक हैं और न ही उन्हें उपरोक्त भूमि प्राप्त करने का कोई अधिकार है- एसडीओ के आदेशों के अनुसार रिडीम की गई भूमि मुक्तसर ने कलेक्टर की 6 अगस्त, 1963 की शक्तियों का प्रयोग किया, जो अवैध और कानून के विरुद्ध है और वादी इसके लिए बाध्य नहीं हैं और न ही कोई विमान- दंतार्थ उक्त भूमि पर कब्जा लेने के हकदार हैं।

(8)एआईआर 1971 एस.सी. 761

उस आदेश के अनुसार, प्रतिवादियों के खिलाफ वादी के पक्ष में लागत के साथ पारित किया जाए।

यह मानते हुए कि मुकदमा 1877 अधिनियम की धारा 42 द्वारा प्रभावित किया गया था, हिदायतुल्लाह, सीजे, जिन्होंने न्यायालय का निर्णय सुनाया, ने कहा: –

पीठ ने कहा, "हमने उस पैराग्राफ को फिर से पेश किया है जिसमें वाद पत्र

में राहत मांगी गई थी। यह देखा जाएगा कि वे न तो अदालत के आदेश को रद्द करने और न ही किसी निषेधाज्ञा के लिए कहा गया, दो राहतें, जिन्हें वे घोषणा के अलावा मामले में पूछने के हकदार थे। इस तरह के मुकदमे को विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 42 द्वारा मारा जाएगा और हम इनकार करने की स्थिति में होंगे; वे इन विशिष्ट राहतों के बिना घोषणा करते हैं। सचमुच! उन्हें केवल आदेश को रद्द करने की मांग करनी थी।

यह मामला वर्तमान से स्पष्ट रूप से अलग है। इसमें एक वैध आदेश जिसके द्वारा वादी बाध्य थे, उनके मुकदमा लाने से पहले अस्तित्व में आ गया था। जैसा कि हिदायतुल्लाह, सीजे ने टिप्पणी की थी, आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना उनके लिए आवश्यक थी। यदि आदेश को कायम रहने दिया गया, तो प्रार्थना की गई घोषणा को प्रदान करना एक भ्रामक और वास्तव में, एक अर्थहीन राहत होगी जो तब तक अप्रभावी होगी जब तक कि आदेश को रद्द नहीं किया जाता। इसलिए, आदेश को रद्द करने की राहत 1877 अधिनियम की धारा -42 के परंतुक के अर्थ के भीतर एक 'और राहत' थी। इस मामले के दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि *जुगराज सिंह का मामला (8)* लेफ्टिनेंट कर्नल जीएस दत्ता के मामले *(7) और दिल्ली के* राज्य बनाम *भारत संघ* (6) *मामले में आदेश के विपरीत कुछ भी नहीं देता है।* और इसलिए, याचिकाकर्ता के मामले में कोई सहायता नहीं है।

(10) बताए गए कारणों के लिए, याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

के.एस.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरूग्राम, हरियाणा